# झारखंड में आदिवासी शिक्षा का महत्व

द्वारा

**संगीता राज ,शोधकर्ता**

**एस.के.एम.यू ,दुमका**

## सार

भारत की नवनिर्मित राज्य ,15 नवंबर 2000 को गठित झारखंड की पहचान यहां की आदिवासी जनसंख्या है | झारखंड की स्थापना के दो दशक पूरे हो जाने पर भी झारखंड में शिक्षा ,स्वास्थ्य,एवं अंधविश्वास का सवाल अभी भी एक महत्वपूर्ण एवं चिंतनीय मुद्दा है | शाब्दिक अर्थ मे आदिवासी शब्द दो शब्दों 'आदि'और 'वासी' से मिलकर बना है जिसका मूल अर्थ है- निवासी | जिसे सभ्यता निर्माताओं ने अंग्रेजी शब्द 'ट्राईब'के मूल लैटिन शब्द 'ट्राइबस' के रूप में व्यक्त किया है | प्रमुख विद्वानों ने इसे निम्नलिखित रूपों में परिभाषित करने का प्रयास किया है |

1 बोआस के अनुसार "जनजाति से हमारा तात्पर्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो सामान्य भाषा बोलता हो ,तथा बाह्य आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए संगठित हो |"

2 जैकब्स तथा स्टर्न के अनुसार , " एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदायों का ऐसा समूह जिसकी सामान्य भूमि हो !सामान्य संस्कृति व सामान्य भाषा हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ ओत प्रोत हो जनजाति कहलाता है |"

झारखंड में 32 समुदाय की जनजातियां पाई जाती है | झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 1003 महिलाएं हैं जबकि देश की अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 989 है | झारखंड की अनुसूचित जनजातियों में उच्च स्तर की लिंगानुपात होने के बावजूद यहां इस समुदाय में साक्षरता दर अत्यंत निम्न है | अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या साक्षरता दर अपने राज्य झारखंड की औसत साक्षरता दर से काफी कम है | इसका अर्थ है शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से झारखंड के आदिवासी अभी बहुत पीछे हैं |

**कीवर्ड** ( शिक्षा, सामाजिक, अनुसूचित जनजाति, साक्षरता, अशिक्षा)

## शोध साहित्य की समीक्षा

डॉ रामकुमार तिवारी ,झारखंड की रूपरेखा

1 जनजातियों के पिछड़ापन का एक महत्वपूर्ण कारक है उनमें निम्न साक्षरता दर का पाया जाना | आंकड़े के अनुसार जनजातियों में साक्षरता की दर वर्ष 1961 में 9.61 प्रतिशत 1971 में 11.64 प्रतिशत 1981 में 17.51 प्रतिशत तथा 1991 में 22 प्रतिशत था | झारखंड की कुल जनसंख्या में साक्षरता का प्रतिशत 1981 और 1991 में क्रमश 28 और 33 प्रतिशत थी किंतु जनजातियों में यह प्रतिशत 17. 5 और 22 प्रतिशत थी | हालांकि हालांकि धीरे-धीरे शिक्षा का प्रसार होता रहा ,परंतु यह बहुत उत्साहवर्धक आंकड़ा नहीं है क्योंकि झारखंड की औसत साक्षरता दर 54 प्रतिशत है | ( 2001 की जनगणना के अनुसार )

2 श्याम कुमार ,झारखंड एक विस्तृत अध्ययन, सफल प्रकाशन | 1988 से ही केंद्र सरकार के सहयोग से साक्षरता मिशन शुरू किया गया, इसके अंतर्गत दुमका और धनबाद जिले को शामिल किया गया | इस अभियान में दुमका और धनबाद में विशेष उपलब्धि हुई |1991 में बिहार शिक्षा परियोजना की स्थापना सोसायटी पंजीकरण एक्ट के तहत हुई | इस परियोजना में यूनीसेफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 3:2:1 है | 1992 में यह योजना प्रारंभ की गई | यह योजना चतरा , रांची, और पूर्वी सिंहभूम में लागू किया गया | इसका उद्देश्य 15- 35 वर्ष आयु वाले निरक्षर वयस्कों को सामान्य शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध कराना था |

3 रामशरण जोशी, आदिवासी समाज और शिक्षा, ग्रंथशिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

वास्तव में आदिवासियों की अपनी सरलता और अज्ञानता ही उनके लिए अभिशाप सिद्ध हुई है | वह अपनी अज्ञानता के चलते चल अचल संपत्ति खोने के साथ-साथ आदिवासियों ने अपना नैतिक बल,साहस ,विरोध और प्रत्याक्रमण की क्षमता को दी है |

## अध्ययन का उद्देश्य

आदिवासी शिक्षा की समस्याओं का विश्लेषण

आदिवासी शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जानकारी देना

शिक्षा का महत्व

**अध्ययन पद्धति:**

इस शोध का अध्ययन वर्णनात्मक एवं सामाजिक विश्लेषणात्मक प्रकृति का है , एवं द्वित्तीयक आंकड़ों पर आधारित समाजशास्त्र विषयों की संदर्भ पुस्तकों एवं समाचार पत्र , जनरल में प्रकाशित लेखों का अध्ययन एवं और विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटा प्रमाणिक स्रोत से लिया गया है |

## परिचय

झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है | बुकानन के अनुसार काशी से बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था | प्राचीन समय में झारखंड में शिक्षा मंदिर ,मठ, मदरसा ,युवागृह,आदि स्थानों में दी जाती थी | जहां छात्र नैतिक शिक्षा ग्रहण करते थे | किसी भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अभाव में झारखंड में अधिकांश जनजाति की अपनी पारंपरिक संस्थाएं थी |जिनमें सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं और संस्कृति और व्यवहार पैटर्न के दायरे में शिक्षा प्रदान की जाती थी विभिन्न जनजातियों की इन संस्थाओं मे घुमकुड़िया ( उरांव ), गीतियोर ( मुंडा), घोटुली ( गौड़ ) आदि संस्थाएं थी | राज्य मेंआधुनिक शिक्षा की आधारशिला अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शासन काल में रखी गई थी | राज्य मे शिक्षा के प्रसार में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ-साथ ईसाई मिशनरियों,भारत राजनीतिज्ञ,एवं एवं स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार सरकार का काफी योगदान रहा |

## अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा :--

शिक्षा के विकास में कर्थवट एवं नील महोदय का विशिष्ट योगदान रहा उन्होंने वर्ष 1831 में झारखंड के रामगढ़ में एक विद्यालय खोलने की कोशिश की | 1834 ईस्वी में चंदेरी गांव में एक स्कूल की स्थापना हुई | एच. रिकेटस के प्रस्ताव पर कैप्टन थॉमस विलकिंग्सन (साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के एजेंट) के द्वारा की गई | छोटा नागपुर के कमिश्नर जे.आर. आउसले ने लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति के तहत 1839 ईस्वी में रांची जिला स्कूल( माध्यमिक स्तर) की स्थापना हुई |

## ईसाई मिशनरियों का योगदान :--

झारखंड में आदिवासियों और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शिक्षा देने के काम में मिशनरी का अभूतपूर्व योगदान रहा है | झारखंड में सबसे पहले विद्यालय खोलने का श्रेय मिशनरी को जाता है | मिशनरी ने बहुत से स्कूल और कॉलेज का निर्माण करवाया | शुरू शुरू में छात्र स्कूल में दाखिला लेने में कुछ खास रूचि नहीं दिखाते थे, और स्कूल संचालकों को इस कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो उन्होंने आदिवासी छात्र छात्राओं को ज्यादा आकर्षित करने के उद्देश्य से विद्यालय में आने वाले हर लड़के - लड़कियों को प्रत्येक सप्ताह के अंत में एक आना या 6 पैसा प्रतिदिन की उपस्थिति की दर से छात्रवृत्ति देना शुरू किया | इससे ज्यादा से ज्यादा छात्र विद्यालय पढ़ने के लिए आने लगे | इसके अलावा घर-घर जाकर मिशनरी के धर्म प्रचारक आदिवासी बच्चों के माता-पिता से मिलकर बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते जिनमें वे कई बार असफल भी हो जाते थे, लेकिन मिशनरी के लोग ने लगातार अपना प्रयत्न जारी रखा और जिससे धीरे-धीरे बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय आने शुरू किए | जिससे स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और झारखंड में स्कूलों की संख्या भी बढ़ गई |

गोस्सनर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च मिशन द्वारा 1944 तक 109 प्राथमिक विद्यालय , 9 माध्यमिक विद्यालय ,और 3 हाई स्कूल की स्थापना की जा चुकी थी , जिसमें कुल छात्रों की संख्या 2257 थी |

सोसाइटी और प्रोपेगेशन ऑफ गोस्पेल मिशन शिक्षा के क्षेत्र में इस मिशन का काफी योगदान रहा राज्य में इस मिशन के द्वारा रांची चाईबासा हजारीबाग में आवासीय विद्यालय स्थापित हुए इस मिशन के द्वारा दो प्रकार के ग्रामीण स्कूलों की स्थापना हुई |

छोटे बच्चों के लिए डे स्कूल ( day school )

कार्यशील विद्यार्थियों के लिए रात्रि पाठशाला ( night school )

एसपीजी मिशन में शिक्षा के विकास के लिए वर्ष 1870-1988 के मध्य 118 स्कूलों का संचालन हुआ |

रोमन कैथोलिक मिशन के 1818-1850 ईसवी में शैक्षणिक कार्य की शुरुआत हुई | 1905 भी में सेंट जॉन स्कूल,1912 ईस्वी में शिक्षण प्रशिक्षण स्कूल नावाटोली और 1914 ईस्वी में उर्स लाइन महिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई | 1947 ईस्वी तक रोमन कैथोलिक मिशन में 697 विद्यालय की स्थापना हुई |

रोमन कैथोलिक मिशन द्वारा 7 जुलाई 1944 ईस्वी में सेंट जेवियर इंटर कॉलेज की स्थापना रांची में हुई | 1948 ईस्वी में इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज में परिवर्तित किया गया |

द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, डॉक्टर कैंपबेल जो इस मिशन से जुड़े थे , उन्होंने संथाली, अंग्रेजी भाषा में शब्दकोश की रचना की | शिक्षा के क्षेत्र में इस मिशन से राज्य के हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया |झारखंड में वर्ष 1915 तक 151 विद्यालय की स्थापना हुई |

डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में हजारीबाग में हुई इसमें सेंट कोलंबा कॉलेज की स्थापना जुलाई 1899 ईस्वी में हजारीबाग में हुई जो उस समय अविभाजित बिहार का सबसे पुराना कॉलेज रहा | इस कॉलेज में प्रथम आचार्य जे. ए. मर्रे (J. A. Murry ) को बनाया गया |1986 से स्नातक स्तर की पढ़ाई यहां होने लगी |

स्वतंत्रता के समय झारखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था , कारण था यहां के लोगों में अशिक्षा, अंधविश्वास , पिछड़ापन ,गरीबी, का व्याप्त होना | यहां की अधिकतर लोग खासकर आदिवासी किसान और मजदूरी का काम कर अपना जीवन यापन करते थे | झारखंड में आदिवासियों का साक्षरता दर झारखंड के औसत साक्षरता दर से काफी नीचे है | 90 के दशक में जब सबके लिए शिक्षा की शपथ विकासशील देशों ने सम्मिलित रूप से ली, तब भारत भी उन देशों में एक था | अतः उस समय भारत सरकार की नजर विशेष रूप से दलित व आदिवासी वर्ग पर पड़ा ,जो अशिक्षित जनता का सबसे बड़ा हिस्सा था | अत: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इन लोगों को शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं |

आवासीय विद्यालय योजना - आवासीय विद्यालय योजना 1 अप्रैल 2002 से कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया था | यह योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, और पिछड़ा वर्ग, के छात्र-छात्राओं के लिए निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना है | झारखंड में 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ,11आश्रम विद्यालय और 125 आवासीय विद्यालय संचालित है | 2019 - 20 से 13 और नए एकलव्य विद्यालय आदिवासी छात्रों के लिए खोले गए हैं |

मुक्त पोशाक वितरण योजना -यह योजना झारखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली गरीब छात्राओं को निशुल्क पोशाक उपलब्ध कराना है |

मुफ्त साइकिल वितरण योजना - साइकिल वितरण योजना 1 अप्रैल 2002 में झारखंड में शुरू की गई | स्कूल और घर के बीच की दूरी की वजह से छात्राओं की पढ़ाई कहीं बीच में न छूट जाए इसे ध्यान में रखते हुए यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई |

फ्री स्कूल किट - स्कूल में छात्रों का 100% जीईआर को प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 2015-16 से निशुल्क स्कूल किट वितरित की जाती है |

विद्यालय छात्रवृत्ति - सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है | कक्षा 1 से 7 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पारिवारिक आय की कोई सीमा नहीं है , जबकि कक्षा 9 से 10 वीं के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.5 लाख और पिछड़े वर्ग के लिए 1.5 लाख की निश्चित पारिवारिक आय सीमा है |

राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देती है, जिसके तहत पहली से दसवीं कक्षा तक के बीच में सरकारी स्कूलों में एनरोल्ड स्टूडेंट को ₹500 से लेकर ₹2250 प्रति छात्र स्कॉलरशिप देती है | वही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अधिकतम ₹5000 से लेकर ₹15000 तक के बीच में दी जाती है | इसके अलावा भी और कई सारी योजनाएं सरकार द्वारा गरीब छात्रों के लिए चलाया जा रहा है जैसे :

आकांक्षा योजना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना

जवाहर नवोदय विद्यालय योजना

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना

मध्याह्न भोजन योजना आदि |

झारखंड प्रदेश में आदिवासी बच्चों को बुनियादी शिक्षा आदिवासी भाषा में ही अब से सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन कराने की सरकारी योजना है | झारखंड राज्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है | नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनकी घर की भाषा में खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही हैं , ताकि झारखंड के बच्चों का शैक्षणिक आधार मजबूत बने | 3 से 9 वर्ष के बच्चों को त्रिभाषा सूत्र के तहत घरेलू भाषा में संथाली, मुंडा,हो,और कुडुख, खड़िया ,जनजातीय भाषा की किताब उपलब्ध कराई जा रही हैं |

त्रिभाषा सूत्र यानी एल -1 एल -2 एल -3 | एल -1 मतलब संबंधित क्षेत्र का मातृभाषा यानी संताली, हो, मुंडा, कुडुख आदि है | एल -2 यानी हिंदी तथा एल -3 का तात्पर्य अंग्रेजी से है | कक्षा एक के बच्चों को 70% शिक्षा उनके घर की भाषा में तथा 30% हिंदी में प्रदान करना है | यहां अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शून्य है | कक्षा दो में बच्चों की घरेलू भाषा में 50% तथा द्वितीय भाषा हिंदी में 50% बोलचाल की भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है , यहां पर भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शून्य है | कक्षा तीन में बच्चों की स्थानीय मातृभाषा में 50% , हिंदी में 30% ,तथा यहां पर अंग्रेजी भाषा को 20% मात्र समावेशित किया गया है |

2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 66.41% था | इसमें महिलाओं का साक्षरता दर 52.04 प्रतिशत, जबकि पुरुष साक्षरता दर 76. 84% थी | 2011 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 57.10% है जो राज्य की कुल साक्षरता दर से 9.31% कम है , वहीं अगर राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो यह आंकड़ा 75.8% है , जबकि अनुसूचित पुरुषों में साक्षरता दर 68. 2% है जो झारखंड की साक्षरता दर से 8.6% कम है | वहीं महिलाओं में साक्षरता दर को देखे तो राज्य में 55.4 प्रतिशत साक्षरता दर है जबकि अनुसूचित जनजाति महिलाओं में साक्षरता दर 46. 2% है जो राज्य की साक्षरता दर से 9.2% कम है

6 जिलों में जनजाति महिला साक्षरता दर के कम आंकड़े बताते हैं कि कोडरमा,साहेबगंज,गोड्डा , पाकुड़, गिरिडीह ,और देवघर जिला में जनजातीय समाज की महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है | महिलाओं की साक्षरता दर कोडरमा में 28.33% ,साहेबगंज में 31.2%, गोड्डा में 32.3% ,पाकुड़ में 32. 3%, गिरिडीह मे 33.3% , और देवघर में 34. 4% है , जो जनजातीय समाज की कमजोर आर्थिक अवस्था को उजागर करती है |

प्रिमिटिव ट्राइब में साक्षरता दर राज्य में सबसे कम :

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आदिम जनजातियों की साक्षरता दर सबसे कम है | जबकि केंद्र सरकार की ओर से विशेष रुप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी की विकास के लिए झारखंड

सरकार को 2015-16 में 1627.37 लाख , 2016-17 मे 3120 लाख और 2017-18 मे 2043.75 लाख रुपये झारखंड सरकार को मिले | रिपोर्ट में पीवीटीजी समूह के आदिम जनजाति पहाड़ियां में साक्षरता दर 25.6%, बिरहोर में 26. 4% , सबर में 26 9%, बैगा में 29.4% , कोरबा में 29.4% ही साक्षरता दर है |

1991 में झारखंड में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 22 प्रतिशत थी जो 2001 मे बढ़कर 47.1 प्रतिशत हुई | इन 10 सालों में 25.1 प्रतिशत की साक्षरता बढ़ोतरी जनजातीय लोगों में हुई , और 2011 में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 57.10 प्रतिशत है |

किंतु जनजातीय समाज में साक्षरता दर राज्य की औसत दर से 9.31 प्रतिशत कम रही है , जो जनजातीय इलाके में शिक्षा की बदहाली को उजागर करती है |

इन आंकड़ों के आधार पर जो तथ्य सामने आते हैं वह है :

1 अनुसूचित जनजातियों में लगातार साक्षरता दर में वृद्धि

2 राज्य के औसत साक्षरता दर की तुलना में आदिवासियों की साक्षरता दर कम होना

3 अनुसूचित जनजातियों में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता दर में बड़ा अंतर होना

इन तथ्यों के आधार पर जो बात सामने आती है निश्चित रूप से वह उत्साहजनक नहीं है , अब प्रश्न उठता है कि वह कौन कौन से कारक है जो आदिवासी समाज में शिक्षा के प्रमुख बाधक है |

जनजातीय समाज में निम्नलिखित समस्याएं प्रमुख रूप से पाई जाती है :

**1 सामाजिक समस्याए --** जनजातीय लोगों में मद्यपान का प्रचलन दीर्घकाल से विद्यमान है | अतः मद्यपान से न केवल उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है , वरन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पारिवारिक कलह भी बढ़ते हैं | अशिक्षा तथा शहरी सभ्यता से दूर, जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों का आर्थिक शोषण कोई नई बात नहीं है | वनों से प्राप्त नैसर्गिक संपदा के लिए व्यापारी, ठेकेदार तथा बिचौलिया द्वारा बराबर उनका शोषण किया जाता है | वनोतपन्न पदार्थ : जैसे चिरौंजी, घी ,शहद, तथा महंगी वस्तुओं का उचित मूल्य आदिवासियों को नहीं मिल पाता है |

**2 धार्मिक समस्याएं --**जनजातियों में धर्म जादू टोने आदि का विशेष महत्व है, पराया बीमार व्यक्ति का इलाज टोने टोटके से किया जाता है | परंतु बाह्य प्रभावों एवं सामाजिक संगठनों की सक्रियता के कारण अब जादू टोने का महत्व कम हो गया है , इसके अलावा आदिवासियों में धर्मांतरण की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है |

**3 राजनीतिक समस्याएं --** आदिवासियों में पहले राजनीतिक जागरूकता प्राय: शून्य के बराबर थी , परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न स्तरों पर आरक्षण प्राथमिकता ,प्रजातांत्रिक, अधिकारों के अंतर्गत चुनने एवं चुने जाने के अधिकार मिलने से वह भी शासन के भागीदारी बन गए हैं |परिणाम स्वरूप में अपनी सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के प्रति उनमें जागरूकता आ रही है |

**भौगोलिक कारण** -- घर से विद्यालय की अधिक दूरी ,नदियों और पर्वतों आदि स्थलाकृतिक की बाधाएं आदि |

**भाषा की समस्या--** झारखंड के अनुसूचित जनजाति विभिन्न समुदायों की अपनी अलग-अलग भाषाएं हैं | अधिकांश आदिवासी हिंदी अंग्रेजी या अन्य भाषाएं बोल और समझ नहीं सकते ,यह उनकी साक्षरता का सबसे बड़ा बाधक है |

**अनुसूचित जनजातियों की कमजोर आर्थिक स्थिति --** अधिकांश जनजातीय समुदायों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संबंधित शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव |

**माता-पिता का दृष्टिकोण** -- औपचारिक शिक्षा के दीर्घकालिक मूल्य के संबंध में जागरूकता का अभाव हैं | क्योंकि शिक्षा कोई तत्काल आर्थिक प्रतिफल नहीं देती है | इसलिए आदिवासी माता-पिता अपने बच्चों को ऐसे पारिश्रमिक प्रदान करने वाले रोजगार में संलग्न करने को वरीयता देते हैं , जिससे नियमित आधार पर परिवार की आय बढ़े |

शिक्षकों के बीच जनजातीय संस्कृति की समझ का अभाव |

**अशिक्षा एवं निरक्षरता की समस्याएं** -- जनजातियों की प्रमुख समस्याएं शिक्षा तथा निरक्षरता से संबंधित है | इनमें निरक्षरता का प्रतिशत आज भी अन्य जातियों की तुलना में काफी अधिक है | अशिक्षा के कारण ही जनजातीय समाज अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं गलत परंपराओं में फंसे हुए हैं | अशिक्षा के कारण ही आदिवासी लोग राष्ट्रीय धारा तथा वैज्ञानिक उन्नति से अलग पड़े हैं |

झारखंड राज्य बने करीब 2 दशक से अधिक बीत गए लेकिन इस अवधि में कहां पहुंचा झारखंड ?

झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किए गए एक रिसर्च के अनुसार संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेजों में आदिवासी (अनुसूचित जनजाति ) कोटे की 91 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती है | राज्य के शिक्षण संस्थानों में आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) के लिए 26 प्रतिशत सीटें आरक्षित है, पर उनमें काफी कम सीटें भर पाती है | दाखिला लेने वाले छात्रों में भी कुछ ड्रॉपआउट हो जाते हैं तथा कुछ कोर्स की अवधि में पास नहीं हो पाते है | रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि इसमें कोर्स पूरा करने वाले छात्रों में से महज करीब 15 प्रतिशत छात्र छात्राओं को ही नौकरी मिल पाती है | ऐसा भी नहीं है , कि यह स्थिति महज इंजीनियरिंग में ही है बल्कि पॉलिटेक्निक , मेडिकल समेत उच्च शिक्षा के सामान्य कोर्स में भी कमोबेश यही स्थिति है |

झारखंड राज्य 2000 में बना | राज्य में शिक्षा का अधिकार संबंधी कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू है | सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ,एवं शत प्रतिशत ठहराव पर बल दिया गया , पर आंकड़ा की माने तो वर्ग -1 से वर्ग -7 तक बच्चों का ड्रॉपआउट 68.39% थी | इससे यह समझना कठिन नहीं है कि जिस समुदाय में इतनी अधिक संख्या में बच्चे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा पास करने के पूर्व की पढ़ाई छोड़ देते हैं, आखिर उच्च शिक्षा में उनकी स्थिति क्या होगी |

यहां पर मैट्रिक स्तर पर 17 भाषाओं की पढ़ाई होती है | झारखंड में जिलावार अधिसूचित 20 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में से 12 की पढ़ाई मैट्रिक का स्तर पर होती है | यदि गत वर्ष यानी 2021 की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के आंकड़े को देखा जाए तो कुल 4.33 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे | इनमें से जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ 62 हजार 545 परीक्षार्थी शामिल हुए | इनमें से करीब आधे यानी 29 011 बच्चे उर्दू के थे | मैट्रिक में जनजातीय भाषा में सबसे अधिक बच्चे संथाली पढ़ने वाले हैं | उक्त परीक्षा में संताली में कुल 11,224 परीक्षार्थी थे | इसी प्रकार जनजातीय भाषा के रूप में खड़िया को 4 जिलों में मान्यता दी गई है , वस्तुस्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में इसके सिर्फ 59 परीक्षार्थी ही शामिल हुए थे | सही स्थिति का अंदाजा इससे भी हैं कि झारखंड में प्रत्येक वर्ष मैट्रिक परीक्षा में करीब चार लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होते हैं | जिसमें 8 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में से पांच हजार से भी कम विद्यार्थी शरीक होते हैं |

आदिवासी में विकास की अवधारणा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आदिवासी संस्कृति के उस पक्ष को कैसे बचाया जाए जो समाज के लिए उपयोगी है , एवं मुख्यधारा की संस्कृति को अधिक समृद्ध कर सकता है और यह भी है कि आदिवासियों के उत्थान के अभिनव आयाम खोलते रहने के साथ-साथ |

अब ऐसा भी नहीं है कि दो दशक पूरा हो जाने के बाद यहां कुछ नहीं हुआ | झारखंड राज्य के विकास की हो या फिर आदिवासी चेतना में सामाजिक , राजनीतिक व सांस्कृतिक उभार का है | हर स्तर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ बदलाव दिख रहा है | सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्य छात्रों के साथ-साथ आदिवासी छात्र भी ले रहे हैं | खासकर मिड- डे-मील योजना , छात्रवृत्ति के साथ ड्रेस एवं किताब कॉपियों की निशुल्क वितरण ने आदिवासियों की आर्थिक दिक्कतों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है | आदिवासियों में शिक्षा के प्रति आई चेतना के कारण उनके शोषण में भी कमी आई है | सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रयासों के कारण कई दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा की नींव पर चुकी है | 2015-20 के दौरान झारखंड में

महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है | 2015 में झारखंड में विश्वविद्यालयों की संख्या 14 थी , वही 2019-20 के दौरान विश्वविद्यालयों की संख्या 32 है | स्कूल भवन बड़ी संख्या में बने, शिक्षक दोगुने हुए पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अभी बड़ी चुनौती है | साक्षरता दर में वृद्धि हुई है लेकिन महिला साक्षरता अभी भी बहुत पीछे है |

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति छात्रों का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात पिछले 5 सालों (2015 - 20) तक में 50.1% की वृद्धि हुई है | वर्ष 2015-16 में एसटी (ST)छात्रों का नामांकन 10.5% था ,वहीं 2020 तक छात्रों का सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 15.6% हो गया | पुरुष एसटी छात्रों सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि वर्ष 2015- 20 के बीच 4.5% हुआ , वहीं महिला एसटी छात्राओं का सकल नामांकन अनुपात (2015--20) के बीच वृद्धि 5.7%हुआ है |

वही 2015-16 में जहां अनुसूचित जनजाति छात्रों उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन 101118 था ,वहीं 2019-20 में छात्रों का नामांकन बढ़कर 153526 है |

## निष्कर्ष:

आदिवासी में विकास की अवधारणा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आदिवासी संस्कृति के उस पक्ष को कैसे बचाया जाए जो समाज के लिए उपयोगी है, एवं मुख्यधारा की संस्कृति को अधिक समृद्ध कर सकता है | और यह भी है कि आदिवासीयों के उत्थान के अभिनव आयाम खोलते रहने के साथ- साथ | इसके लिए जनजातियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता हैं | दूरस्थ और अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान की आवश्यकता है | इसके अतिरिक्त स्थानीय जनजातियों को शिक्षण कार्य में प्राथमिकता प्रदान करना एवं आदिवासी क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय स्थानीय रीति-रिवाजों को महत्व दिया जाना महत्वपूर्ण है |

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1 डॉ रामकुमार तिवारी , झारखंड की रूपरेखा

2 श्याम कुमार, झारखंड एक विस्तृत अध्ययन, सफल प्रकाशन

3 रामशरण जोशी, आदिवासी समाज और शिक्षा

5 Vaiganikchetna.com> शिक्षा

6 www.iasbook.com>Home >Blog

7 www.jagran.com.jamshedpur 10 Aug 2021

8 ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

9 newswing.com>adivasi- are-facing- poo...11.1.2019